hati, Calcutta and Kerala and the duties of the Chief Justices are being performed by the seniormost puisne Judges of the respective High Courts. The question of appointment of the Chief Justices of Jammu & Kashmir and Gauhati High Courts is engaging the attention of the Government in consultation with the authorities concerned. The vacancies in the offices of Chief Justices of the High Courts of Calcutta and Kerala are of very recent occurrence. The Chief Justice of Madras High Court had been transferred to Kerala but on a Writ Petition being filed, the Supreme Court has ordered that *status quo* be maintained. The Chief Justice of the Madras High Court has not joined at Kerala and continues to hold the office of Chief Justice of Madras. As he has proceeded on leave, the seniormost puisne Judge has been appointed to perform the duties of Chief Justice while the latter is on leave. The question of filling the vacancy of the Chief Justice of Calcutta High Court is engaging the attention of Government.

Setting up of Polyester Staple Fibre plant at Bongaigaon, Assam

646. SHRI ROBIN KAKATI: Will the Minister of PETROLEUM ,CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under Government's consideration to set up a Polyester Staple Fibre Plant at Bongaigaon in Assam; and

(b) whether Central Government have received any request from the Government of Assam in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b) M/s. Bongaigaon Refinery and Petrochemicals Ltd. are in the process of setting up a Polyester Staple Fibre Project at Bongaigaon in Assam with a capacity of 30,000 tonnes per annum.

Setting up a Polyester Staple Fibre Plant in Delhi

647. SHRI ROBIN KAKATI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Polyester Staple Fibre Plant is proposed to be set up in Delhi by the Bongaigaon Refineries and Petrochemicals Limited; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सोवियत रूस से 1000 मै० वा० का ताप विद्युत संयंत्र

648. **श्री नागेश्वर प्रसाद शाही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने भारत को 1000 मै० वा० के एक ताप विद्युत संयंत्र की पेशकश के लिए प्रस्ताव किया है, हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार इस पेशकश से लाभ उठाने का विचार रखती है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। 10 दिसम्बर, 1980 को भारत के प्रधानमंत्री तथा सोवियत राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित, भारत और सोवियत संघ के बीच सम्पन्न हुए आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग करार के अन्तर्गत, सोवियत सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ (3000 मेगावाट तक विस्तार किए जा सकने की संभाव्यता वाले) 1000

मेगावाट की क्षमता के एक समेकित ताप विद्युत संयंत्र के तथा इसी के अनुसार पारेषण तथा कोयले की सुविधाओं के निर्माण कार्य के वित्त पोषण के लिए ऋण देगी ।

सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में वैधान में स्थापित की जाने वाली सुपर ताप विद्युत परियोजना के 1000 मेगावाट के प्रथम चरण का कार्य सोवियत सहायता से हाथ में लिया जाएगा । यह परियोजना केन्द्रीय सेक्टर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा निष्पादित की जाएगी ।

परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार कर ली गई है तथा केन्द्रीय विदयुत प्राधिकरण में उसका तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है। उपरोक्त करार पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद परि योजना के संबंध में आगे कार्रवाई करने के बारे में, दोनों देशों के विशेषज्ञों के बीच बैठक भी हुई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म मेले का आयोजन

649. **श्री नागेश्वर प्रसाद शाही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म मेला आयोजित करने के प्रश्न की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने कौन-कौन-सी सिफारिशें की हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि समिति ने यह सुझाव दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म मेले सरकार के फिल्म मेला निदेशालय द्वारा आयोजित नहीं किए जाने चाहिए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने के प्रश्न की जांच करने के लिए सरकार ने कोई विशिष्ट समिति नियुक्त नहीं की थी। तथापि राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्यदल, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ इस मामले की भी जांच की थी. ने सिफारिश की है कि :—

(1) भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए ; और

(2) प्रतियोगी समारोह के बजाय, भारत को हर वर्ष गैर-प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करना चाहिए ।

Change in National Legal System

650. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:
SHRI RAMESHWAR SINGH:
SHRI ROSHAN LAL:
SHRIMATI AMARJIT KAUR:
SHRI RAMANAND YADAV:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to evolve a new national legal system without Western influence by combining Islamic jurisprudence and Hindu law (common Hindu and Muslim Law) which was the consensus emerged on the last day of the three days' International Seminar "Islamic contribution to the culture and civilisation of the World with special reference to India" held last month at New Delhi;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if the answer to the part (a) be in the negative what are Government's views on the subject and on the need for universal jurisprudence, common to all people?

THE MINISTER OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHIV SHANKER): (a) The International Seminar on "Islamic Contribution to the Culture and Civilization of the World with special reference to to India" was held last